[श्री राम नरेश यादव]

उन्होंने और अधिकारियों ने कहा कि सन 1993 में शुरू होगा । मैं इसलिए कहा रहा हूं कि उसके किनारे मऊ रेलवे जंक्शन भी है, शाहगंज रेलवे जंक्शन भी है और उसके बीच में बहुत से बुनकरों के बहुल क्षेत्र हैं जैसे मुबारकपुर, खैराबाद, मोहम्मदाबाद है, कुछ दूरी पर दोहरीघाट है और मुबारकपुर की बनारसी साडी बनारस में आकर उस नाम से मशहूर है । उसका निर्यात भी किया जाता है, विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है । वहां पर उसके किनारे दो-दो अरबी और फारसी के विद्यालय भी हैं जहां कि दूसरे देशों के लड़के आ करके उसमें विद्या अर्जित करते हैं . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : प्लीज कन्कलूड ।

श्री राम नरेश यादव : दोनों तालीम भी अर्जित करते हैं । वहां पर सारी स्थिति है । इस बात को ध्यान में रख करके और पूर्वांचल के विकास के लिए मेरी सरकार से मांग यह है कि इस काम को जो निर्णय सरकार ने लिया है जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए और जल्दी जल्दी प्रारंभ करने की आवश्यकता है 1993 के प्रारंभ में अवश्य यह काम शुरू हो जाना चाहिए और साल भर के अंदर इस काम को कर देना चाहिए ताकि पूर्वांचल का विकास हो सके । हां के क्षेत्र का विकास हो सके । यह बड़े दिनों की जो मांग है उसकी पूर्ति होने से उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा । यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है ।

श्री मुहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश) दो मिनट . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन्तप्पा) : स्पेशल मेंशन के लिए तीन मिनट हैं, आपको दो मिनट कैसे मिलेंगे ।

श्री मोहम्मद मसूद खान : अच्छा, एक मिनट ।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमनतप्पा) : ठीक है ।

श्री मोहम्मद मसूद खान : मान्यवर, शाहगंज-जोनपुर, और गोरखपुर और फिर शाहगंज-फैजाबाद-गोरखपुर इस तरह से बड़ी लाइन है बीच में शाहगंज से लेकर मऊ तक यह छोटी लाइन है । वहां इस वक्त आजमगढ़ में 5 राज्य सभा के मेम्बर हैं, पूरे हरियाणा में 5 राज्य सभा सीट है, 3 लोक सभा के मेम्बर हैं, ये 8 आदमियों का आने-जाने से सिर्फ थोड़े से पीस की वजह से यह जो छोटी लाइन है, बड़ी लाइन में परिवर्तन नहीं हो रहा है पता नहीं कितने लोगों ने उम्मीद बधाई है तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि केन्द्र सरकार इस पर फौरन काम शुरू कर दे ताकि लोगों को यह यकीन तो हो जाय कि वाकई इसको छोटी लाइन से बड़ी लाईन में बदलेंगे और पूरे जिले को आराम और सहूलियत जो आने जाने की है वह इससे मिलेगी वरना कहीं लोग आ-जा नहीं सकते । जहां 6 घंटे में जाना है वहां 24 घंटे लग रहे हैं । तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी ऐसे हालात से वाकिफ होंगे आप खुद निर्देश दे दीजिये कि जल्दी से काम शुरू हो ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) मैं भी एसोसिएट करता हूं ।

STATEMENT BY DIRECTORS (HEALTH), DELHI ADMINISTRATION AGAINST NEHM

श्री जगन्नाथ सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक नवीन चिकित्सा पद्धति जिसे इलैक्ट्रोपैथी के नाम से जाना जाता है एन०ई०एच०म० आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा उसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । 9-7-92 को दिल्ली के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में निर्देशक

स्वास्थ्य सेवायें दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रैस विज्ञप्ति जारी की थी कि एन०ई० एच०एम० ग्राफ इंडिया जनकपुरी नई दिल्ली संस्था द्वारा किये गये सभी कार्य प्रबंध व जालसाजी है। इसमें इन्होंने भारत सरकार से भी सलाह करके यह विज्ञप्ति जारी की थी, जब कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14-6-91 को उक्त संस्था को अधिकृत किया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 25-5-92 को ही इस संस्था के प्रचार-प्रसार के लिये निर्देश जारी किया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर किसी प्रकार के आक्षेपन करे। लेकिन इसके बावजूद भी, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी निर्देशक, दिल्ली प्रशासन द्वारा कोर्ट की अवमानना करते हुए इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी की गई। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के भ्रामक जो निर्देशक द्वारा प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई है उसके संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी हों तथा इस प्रकार की प्रैस विज्ञप्ति न जारी करते हुए शंका का समाधान करें ताकि जो हजारों विद्यार्थी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनका भविष्य इस पर निर्भर है कि उनका आगे का निर्माण किस प्रकार से होगा, मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस प्रकार से निर्देश देकर विज्ञप्ति जारी करे।

ALLOCATION OF FOODGRAINS TO MAHARASHTRA FROM THE CENTRAL POOL

SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to raise a very vital issue, through you, about the allocation of foodgrains to Maharashtra from the Central pool. In view of the drought situation faced by a large parts of the State, the State Government has already requested the Centre for stepping up the State's monthly allocation of wheat and rice to 1.50 lakh tonnes and 0.75 lakh tonnes respectively. Since there has been a substantial fall in the production of foodgrains within the State, the marginal farmers and the agricultural labourers etc. will also be compelled to turn to the PDS for their requirements. As per the latest estimate of the Agricultural Department, the shortfall in kharif production is expected to be approximately 22 lakh tonnes as compared to the previous year and in regard to the rabi production, even though no assessment has yet been made by the Agricultural Department, it appears that the shortfall in rabi production will not be less than 15 lakh tonnes. The shortfall in production of foodgrains within the State is likely to be anything in excess of 30 per cent as compared to last year. Since there has been such a huge shortfall in production, the cultivators' own production, which was meeting approximately 63 per cent of the requirements, will be subjected to very severe limitations and it will correspondingly result in increased pressure on the PDS. Because of the drought situation, the presence of labourers on the relief work has also increased manifold. As per the estimate of the Planning Department, the State would need to provide 2.2 crore mandays per month for the next six or seven months since there is going to be no procurement of jowar under the Price Support Scheme this year. There would naturally be a demand for distribution of wheat to the labourers working on the EGS work. The State Government has therefore requested the Centre for separate allocation of 25,000 tonnes of wheat per month for distribution to the labourers engaged on the relief work. As a result of the State Government's persistent requests, the Central Government has given an additional allocation of 13,000 tonnes of wheat and 37,000 tonnes of rice for January 1992, raising the State's monthly allocation to 2.13 lakh tonnes. Again, for February 1992, the Government of India has given an increased allocation of 2.05 lakh tonnes of rice and wheat. With these additional allocations, it will be possible to meet the increasing demand of Bombay, Thane, rationing areas and drought affected areas.